

□□□□ □□□□

जनसत्ता 25 जुलाई, 2014 : पछिले दिनों दो ऐसी खबरें आरंभ, जो किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर तमाचे की तरह हैं।

पहली खबर थी बंगलुरु के □ कसकूल में छह साल की मासूम के साथ वहीं के दो कर्मचारियों द्वारा बलात्कार की। दूसरी खबर बलात्कार की केशशि और क्तल की है। यह वारदात लखनऊ के पास मोहनलालगंज में हुई, जहां दो बच्चों की मां के साथ बलात्कार की केशशि की गई और नाकम रहने पर वहशयिाना तरीकेसे पीट-पीट कर उसकी हत्या करने के बाद □ कसकूल के पास बगैर कर्मियों के पेंक दया गया। □ कशख्स ने इस महला के साथ दरदिगी की सारी हदें पार कर दीं। पोस्टमार्टम की रपौर्ट से जो सच सामने आया वह दलि दहलाने वाला है। आरोपी ने महला के गुप्तांग समेत पूरे शरीर पर गहरे जख्म कीं। पुलसि के मुताबकि जसि अस्पताल में महला कम करती थी उसके पास की इमारत के गार्ड ने इस वारदात के अंजाम दिया।

इन दोनों खबरों क सरोकार देश के हर सूबे से है। हर घर से है। हर माता-पति से है। बंगलुरु में छह साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल में बलात्कार की खबर सामने आने के बाद वहां के अभिभावकों में यह चति ब। गई है क पता नहीं स्कूल के वे कर्मचारी कब से और कतिनी बच्चियों क यौन शोषण या फिर छे। छा। कर रहे थे। क्या कुछ अन्य अभिभावकों के अपनी बच्चियों के साथ छे। छा। की नापाक हरकतों की जानकारी थी और वे बदनामी के डर से मामले के छोटा मान कर भुला चुके थे!

स्कूलों में बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों में अक्सर यह देखने में आता है क जब माता-पति शकियत लेकर जाते भी है तो स्कूल प्रशासन जांच की बात कह कर मामले के दबा देता है। परोक्ष रूप से अभिभावकों के भी स्कूल क नाम खराब होने की दुहाई या धमकी देकर मुंह बंद रखने की हदियत दी जाती है। बच्चों के खलिाफ यौन शोषण के रोक्ने के ल। लागू हु। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेस्ट सेक्सुअल अप्रेस □ क्ट (पॉक्सो) में आरोपियों के बचाने वालों या मामले के दबाने की केशशि करने या फिर मामले बगि। ने वालों के ल। महज छह महीने की सजा क प्रावधान है, लेकिन स्कूल या संस्थान के खलिाफ किसी कर्रवाई क प्रावधान नहीं है। इस वजह से स्कूल प्रशासन ज्यादातर ऐसे मामलों के आपसी समझौतों से दबा देने की केशशि करता है।

समान्यतया अभिभावक भी बच्चों के स्कूल में आगे दक्लि न हो, यह सोच कर हालात से समझौता कर लेते हैं। इसी समझौते से अपराधियों के ताक्त मलिती है। उन्हें लगता है क स्कूल परसिर में अपराध करने से प्रशासन उसके दबाने में जुट जा। गा। लहिाजा वे इस तरह के अपराध के ल। स्कूल के केने-अंतरे के ही चुनते हैं। बंगलुरु के स्कूल में हुई वारदात में इस बात की भी प। ताल होनी चाह। क क्या वहां बच्चियों के यौन शोषण या छे। छा। की कोई शकियत पहले आई थी और स्कूल प्रशासन ने कर्रवाई नहीं की थी।

अगर ऐसी बात सामने आती है तो स्कूल के कर्ताधरताओं के खलिाफ भी पॉक्सो की धाराओं में मुक्दमा दर्ज किया जाना चाह।। इस बात की भी जांच होनी चाह। क आरोपी ने स्कूल में बच्ची के साथ बलात्कार किया तो स्कूल प्रशासन के इस बात की भनक लगी थी या नहीं और उसकी क्या भूमकि थी।

स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण के वारदात के अंजाम देने वाले अपराधी दरअसल यौन कुंठा केशकिर होते हैं और मानसिक रूप से विकृत भी। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे अपराधी यौन आनंद के लिए बच्चों को अपना शक्ति बनाते हैं।

यह एक ऐसी मानसिकता है, जो अपराधी के वारदात अंजाम देने के बाद एक खास किस्म का रोमांच देती है। इस तरह के अपराधी, आम अपराधियों से ज्यादा शातरि होते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि स्कूल उसके अपराध के तुल नहीं देगा। लहाजा वे अपराध के स्कूल परिसर में अंजाम देने से नहीं हचिक्ते।

चंद महीने पहले दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल के स्टाफूम में कई बच्चियों के यौन शोषण की खबर आई थी। दिल्ली में ही एक कैब ड्राइवर महीनों तक एक बच्ची का यौन शोषण करता रहा था। सवाल यह है कि स्कूल की क्या जम्मेदारी है। क्या कोई भी स्कूल यह कह कर पल्ला झा सकता है कि अमुक शख्स ने वारदात के अंजाम दिया इसलिए। कानून के हिसाब से उसके सजा मलिंगी। स्कूल की यह जम्मेदारी भी है कि उसके परिसर में या फिर स्कूल आने और जाने के वक्त बस में बच्चे सुरक्षित रहें। बच्चों की समय-समय पर काउंसलिंग भी होनी चाहिए, ताकि उनके खिलाफ हो रहे इस तरह के अपराध उजागर हो सकें।

बच्चों को इस तरह के अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूल के साथ-साथ अभिभावकों को भी जम्मेदारी लेनी होगी। अभिभावकों को तो अपराध के बाद साहस के साथ सामने आना होगा।

इस तरह के अपराध को रोकने के लिए कानून से ज्यादा जरूरी है जागरूकता। स्कूलों में एक नियमित अंतराल पर शक्ति के लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे जागरूक हो सकें। कानून का भय और समाज में जागरूकता बढ़ाकर ही बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे घनिने कृत्य रोके जा सकते हैं। इस काम में देश के हर नागरिक की जम्मेदारी है कि वह अपनी भूमिका निभाए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो देश के भविष्य को बेहतर नहीं बना सकते हैं। बच्चों को देश में सुरक्षित माहौल देना हमारा दायित्व ही नहीं कर्तव्य भी है।

मलेशियाई विमान हादसे में करीब तीन सौ लोगों के मारे जाने की खबर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मचे कोलाहल और शोरगुल के बीच दो दिनों तक राष्ट्रीय मीडिया इन दो खबरों को उस आवेग से नहीं उठा पाया, जिसकी ये हक्दार है। देर से ही सही, मीडिया ने इस ओर ध्यान दिया। लखनऊ का हत्याकांड दिल्ली के नरिभया कांड जैसा ही जघन्य है। दिल्ली में नरिभया बलात्कार के वक्त इस घनिनी वारदात के खिलाफ माहौल बनाने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई थी और लगातार कवरेज की वजह से सरकार बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून बनाने को मजबूर हुई थी। सोनिया गांधी से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सहित तक के सामने आकर बयान देना पड़ा था। बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा के लिए न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा के सुझावों पर कानून में बदलाव की गई थी, पर चर्चा का सबब तो कि कानून के बावजूद ऐसे अपराधों पर अंकुश नहीं लग पाना भी है।

दरअसल, अगर गहराई में विचार करें तो बलात्कार हमारे समाज का एक ऐसा नासूर है, जिसका इलाज की कानून के अलावा हमारे रहुमाओं की इससे नबिटने की प्रबल इच्छाशक्ति का होना भी है। बलात्कार से नबिटने के लिए समाज के रहुमाओं की इच्छाशक्ति तो दूर की बात है, जरा महिलाओं को लेकर उनके विचार देखें। शिया धर्म गुरु क्लबे जव्वाद कहते हैं- लीडर बनना औरतों का काम नहीं है, उनका काम लीडर पैदा करना है। कुदरत ने, अल्लाह ने उन्हें इसलिए बनाया है कि वे घर संभालें और अच्छी नसूल के बच्चे पैदा करें। राम जन्मभूमि न्यास के महंथ नृत्यगोपाल दास की बात सुनी : महिलाओं को अक्ले मठ, मंदिर और देवालय में नहीं जाना चाहिए। अगर वे मंदिर, मठ या देवालय जाती हैं तो उन्हें पति, पुत्र या भाई के साथ ही जाना चाहिए, नहीं तो उनकी सुरक्षा के खतरा है।

अब जरा महिलाओं के लेकर राजनेताओं के वचन जान लेते हैं। लंबे समय तक गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस नेता दगिंबर कमत ने कहा था: महिलाओं के राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीति महिलाओं के क्रेजी बना देती है। समाज के बदलाव में महिलाओं की महती भूमिका है और उन्हें आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सहि यादव का बयान: अगर संसद में महिलाओं के आरक्षण मिला और वे संसद में आरंभ तो वहां सीटियां बजेंगी। पूर्व केयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने तो सारी हदें तोड़ते हुए कहा था कि: बीवी जब पुरानी हो जाती है तो मजा नहीं देती है। इन बयानों के देख कर ऐसा लगता है कि महिलाओं के प्रति हमारे समाज का सोच धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ कर तकरीबन एक है और यही सोच महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की जड़ में है।

धर्मगुरुओं और नेताओं के इस तरह के बयानों से समाज के कम जागरूक लोगों में यह बात घर कर जाती है कि महिलाओं को तो मजा देने के लिए है या मजे की वस्तु है। इस तरह के कुत्सित वचन जब मन में बैठते हैं तो वे महिलाओं के प्रति अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। उन्हें इस बात से बल मिलता है कि उनके नेता या गुरु तो महिलाओं के बराबरी का दर्जा देते ही नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय भी समय-समय पर बलात्कार के खिलाफ चिंता जता चुका है। कुछ वक्त पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह जानना चाहा था कि क्या समाज और व्यवस्था में कोई खामी आ गई है या सामाजिक मूल्यों में गरिबट आती जा रही है या पर्याप्त कानून नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कानून को लागू करने वाले इसे ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं। कानून लागू करने वालों की बलात्कार के लेकर क्या राय है, वह मुलायम सहि यादव बता चुके हैं। मुलायम सहि यादव ने बलात्कार के बारे में बहुत ही लापरवाह तरीके से कहा कि लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार हो और उसके मुखिया कौन कौन से गलतियां हो जाती हैं तो फिर तो इस तरह की 'गलतियों' को पुलिस भी उसी आलोक में देखेगी और तपस्तीश करेगी।

बलात्कार के खिलाफ कानून लागू करने वालों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का सवाल उचित है। इसके बारे में पूरे समाज को गंभीरता से विचार करना होगा। समाज के हर तबके के लोगों को बलात्कार के इस नासूर के खिलाफ एकजंठ छेनी होगी, ताकि हमारी बेटियां और बहनें महफूज रह सकें। राजनीतिक बरिदरी को संवेदनशीलता दिखाते हुए इस बारे में आगे आकर पहल करनी होगी।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>